शनिवार

22 अगस्त 2026

- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 210
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

चार बाइकों की हुई आमने-सामने भिड़ंत

तीन युवकों की मौत कई घायल

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। कलियर रोड पर बीती रात चार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गयी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार जारी है।

बताया जा रहा है कि दुर्घटना रात करीब साढ़े दस बजे हुई। चार बाइक आपस में टकरा गईं, जिससे सभी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कलियर कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस के अनुसार, हादसे में अयान (18), पुत्र शहजाद, निवासी बिजौली, राजू (24), पुत्र कदम सिंह, निवासी रहमतपुर और राजीव (22), पुत्र मोलाड, निवासी रहमतपुर की मौत हुई है। वहीं घायलों में आदित्य (25), पुत्र सुरेंद्र, निवासी खंजर रोड और साहबान, पुत्र मुराद, निवासी बिजौली समेत अन्य युवक शामिल बताए गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइकों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी आवाज आसपास के इलाके में सुनाई दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और राहत-बचाव में जुट गए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

60 की उम्र में नौकरी खत्म, अफसरों के लिए कुर्सी हाजिर!

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की एक अजीब कहानी है। कर्मचारी की उम्र 60 साल होती है, फाइलों में सेवा समाप्त हो जाती है, पेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ अफसरों की सरकारी पारी खत्म नहीं होती। कुर्सी बदल जाती है, पदनाम बदल जाता है, कभी सलाहकार तो कभी विशेषज्ञ, कभी आयोग तो कभी किसी समिति में नई भूमिका मिल जाती है। यानी सरकारी नौकरी का कैलेंडर आम आदमी के लिए चलता है, लेकिन कुछ खास अफसरों के लिए शायद अतिरिक्त पन्ने भी रखे गए हैं। सवाल यह नहीं है कि किसी सेवानिवृत्त अफसर की विशेषज्ञता का इस्तेमाल क्यों किया जाए। सवाल यह है कि किस आधार पर, कितने समय के लिए और किस पारदर्शी प्रक्रिया के तहत? उत्तराखंड में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की जनहित और अपरिहार्यता की स्थिति में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। शासन के एक आदेश में सलाहकार, परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी और विशेषज्ञ समन्वयक जैसे पदों पर संविदा के आधार पर तैनाती की व्यवस्था का उल्लेख है।

यहीं से असली सवाल पैदा होता है। अगर सरकार को किसी अफसर का अनुभव इतना जरूरी लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसे सरकारी काम सौंपना पड़े, तो फिर क्या राज्य में नई पीढ़ी के अधिकारियों और विशेषज्ञों की कमी है? और अगर कमी है तो उसे दूर करने की योजना क्या है? उत्तराखंड का युवा नौकरी के लिए परीक्षा देता है। हजारों युवा सालों तैयारी करते हैं। रिक्तियों का इंतजार करते हैं। भर्ती परीक्षाओं की तारीख देखते हैं। कभी परीक्षा देती है, कभी परिणाम का इंतजार होता है। दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था में ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें रिटायर होने के बाद भी अनुभवी अफसरों के लिए सरकारी दरवाजे बंद नहीं होते।

- आमजन के लिए उम्र की सीमा, साहबों के लिए आजीवन कुर्सी
- कभी सलाहकार तो कभी विशेषज्ञ, पद बदलते हैं पर चेहरा वही
- पेंशन भी जेब में और भारी-भरकम संविदा का वेतन भी जारी
- अफसरों के लिए अनलिमिटेड एक्सटेंशन पर उठे गंभीर सवाल

यह विरोधाभास सवाल पूछता है। क्या सरकारी व्यवस्था अनुभव के नाम पर एक ही चेहरे को बार-बार मौका देती रहेगी? सरकार कह सकती है कि अनुभवी अफसरों की जरूरत है। बिल्कुल है। अनुभव किसी भी प्रशासन की पूंजी है। लेकिन अनुभव और स्थायी सरकारी पुनर्वास में अंतर है। किसी विशेष परियोजना के लिए विशेषज्ञ की जरूरत हो तो निश्चित अवधि की नियुक्ति समझ में आती है। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद लगातार नई जिम्मेदारियां मिलती रहें तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकारी व्यवस्था में पदों का एक अनौपचारिक पोस्ट-रिटायरमेंट क्लब तैयार हो रहा है? और यह सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है। सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन यह व्यवस्था कई बार अपना रास्ता खोज लेती है।

लोकतंत्र में कुर्सी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती। सरकारी पद जनता के पैसे से चलते हैं। इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि रिटायरमेंट के बाद किसी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति क्यों की गई, उसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या रही, कितने उम्मीदवारों पर विचार हुआ और उसकी नियुक्ति की समयसीमा क्या है। वरना विशेषज्ञता शब्द धीरे-धीरे पहचान का दूसरा नाम बन सकता है। उत्तराखंड जैसे युवा राज्य में यह बहस और जरूरी है। यहां बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत सिर्फ नौकरी की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की समानता को लेकर भी है। जब युवा देखता है कि एक ओर सरकारी पदों के लिए उम्र सीमा खत्म हो जाती है और दूसरी ओर कुछ रिटायर अफसरों के

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

सीमा पर सहमति, रिश्तों में भरोसा

भारत और नेपाल के बीच सीमा केवल नक्शे पर खिंची कोई लकीर नहीं है। यह रिश्तों, रोजमर्रा की आवाजाही, कारोबार, संस्कृति और सदियों पुराने सामाजिक संपर्क की साझा जमीन है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बनी सहमति का महत्व सामान्य कूटनीतिक बैठक से कहीं बड़ा है। देहरादून में 20-21 अगस्त को हुई भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में सीमा पार अपराध, सीमा अवसंरचना, एकीकृत जांच चौकियों, सड़क-रेल संपर्क, अतिक्रमण और सीमा स्तंभों के रख-रखाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई तथा दोनों देशों ने सहयोग मजबूत रखने पर सहमति जताई। भारत-नेपाल सीमा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी खुली प्रकृति है। यही खुलापन दोनों देशों की ताकत भी है और चुनौती भी। सामान्य नागरिकों की आवाजाही और सामाजिक रिश्तों के बीच तस्करी, अवैध गतिविधियों और सीमा पार अपराध के रास्ते खुलना दोनों देशों की चिंता है। इसलिए सुरक्षा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि सीमा को अचानक दीवार में बदल दिया जाए। असली चुनौती यह है कि सीमा सुरक्षित भी रहे और दोनों देशों के नागरिकों की ऐतिहासिक सहजता भी बनी रहे। देहरादून की बैठक से एक महत्वपूर्ण संदेश यह निकलता है कि भारत और नेपाल ने सीमा संबंधी सवालों को टकराव के बजाय संवाद और संस्थागत तंत्र के जरिए हल करने का रास्ता चुना है। सीमा स्तंभों के रखरखाव और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर तकनीक तथा बेहतर समन्वय का इस्तेमाल विवादों को स्थानीय तनाव बनने से रोक सकता है। हाल में दशगजा क्षेत्र में अतिक्रमण की पहचान के लिए ड्रोन मैपिंग पर सहमति की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन कागज पर बनी सहमति तभी सार्थक होगी जब वह सीमा पर दिखाई भी दे। सीमा चौकियों की क्षमता बढ़ाना, आधुनिक निगरानी व्यवस्था विकसित करना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा के नाम पर सीमा से जुड़े आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के लिए इस बैठक का महत्व और अधिक है। राज्य की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और सीमांत क्षेत्रों की भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए सीमा सुरक्षा को केवल पुलिस या सुरक्षा बलों का विषय मानना पर्याप्त नहीं है। सीमांत गांवों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं, जिस सीमा पर गांव मजबूत होंगे, वहां सीमा प्रबंध न भी अधिक प्रभावी होगा। भारत और नेपाल के रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी जनता के बीच का भरोसा है। इसलिए सीमा सुरक्षा की हर नीति में स्थानीय समाज को भागीदार बनाना होगा। दोनों देशों के बीच यदि सुरक्षा सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक संपर्क और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलनी चाहिए। आज जब दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, भारत और नेपाल के लिए आपसी भरोसा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सीमा पर चौकसी जरूरी है, लेकिन रिश्तों में संदेह नहीं। सुरक्षा मजबूत हो, मगर संवाद कमजोर न पड़े। यही भारत-नेपाल संबंधों की सबसे बड़ी कसौटी है। देहरादून की बैठक को इसलिए केवल सीमा सुरक्षा की बैठक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह इस बात की परीक्षा भी है कि दोनों देश अपनी साझा सीमा को तनाव की रेखा बनाने के बजाय सहयोग का गलियारा बना सकते हैं या नहीं। सहमति हुई है और अब उसकी असली परीक्षा जमीन पर है।

क्षेत्राधिकारी ने किया छाम थाने का किया अर्द्धवार्षिक किया निरीक्षण

संवाददाता

टिहरी। क्षेत्राधिकारी चंबा महेश लखेडा ने छाम थाने का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिये। आज यहां क्षेत्राधिकारी चंबा महेश लखेड़ा द्वारा थाना छाम का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में रखे समस्त शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस कर्मचारियों से शस्त्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए शस्त्र प्रशिक्षण भी कराया गया। शस्त्रों से संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर उनमें आवश्यक एवं पूर्ण प्रविष्टियां सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर स्थित भोजनालय/मैस, साफ-सफाई व्यवस्था, आपदा प्रबंधन से संबंधित उपकरण एवं सामग्री तथा क्राइम किट बॉक्स का भी निरीक्षण किया गया। थाना जीपी लिस्ट के अनुसार उपलब्ध समस्त सरकारी सामान का भौतिक मिलान कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान थाना कर्मचारियों का सम्मेलन लेकर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त थाना स्तर पर लंबित विवेचनाओं, शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं विभिन्न पोर्टलों पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। क्षेत्राधिकारी द्वारा सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता एवं अनुशासन बनाए रखने, जनशिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने तथा आमजन के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के अवसर पर थानाध्यक्ष छाम दिलवर सिंह नेगी सहित थाना छाम का समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा।

बेटी का न्याय बनाम 'सियासी जंग'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। अंकिता प्रकरण उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक मुकदमा नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है, जो एक बेटी के परिवार से लेकर पूरे समाज तक फैला हुआ है। ऐसे मामले में सबसे जरूरी चीज है न्याय। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्याय की इस लंबी यात्रा के बीच राजनीति लगातार अपना रास्ता खोज लेती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अंकिता प्रकरण में सीबीआई जांच को लेकर सरकार और जांच एजेंसी की भूमिका सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है और केंद्रीय जांच ब्यूरो तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार जांच कर रही है। यहीं से असली सवाल पैदा होता है कि क्या किसी जांच की दिशा बयानबाजी से तय होगी या सबूतों से? किसी भी आपराधिक मामले में अदालत के सामने आरोप नहीं, साक्ष्य टिकते हैं। जांच एजेंसी का काम प्रेस कांफ्रेंस में फैसला सुनाना नहीं, बल्कि उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों, बयानों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की पड़ताल करना है। सीबीआई हो या कोई दूसरी जांच एजेंसी, उसकी जांच का अंतिम मूल्यांकन अदालत में होना है। लेकिन राजनीति को अदालत का इंतजार कम ही पसंद आता है।

एक तरफ कांग्रेस सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ भाजपा उन सवालों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रही है। टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर बढ़ता जा रहा है। मगर इस शोर में सबसे महत्वपूर्ण आवाज कहीं पीछे छूटने का खतरा है अंकिता के परिवार की न्याय की आवाज। कांग्रेस यदि सीबीआई जांच पर सवाल उठाती है तो उसे सिर्फ राजनीतिक बयान

◆अंकिता भंडारी केस में आखिर कब तक चलेगी बयानबाजी
◆सीबीआई जांच पर खिंची तलवारों के बीच सवाल दरकिनार
◆अंकिता की आत्मा को न्याय चाहिए, राजनीति की रोटियां नहीं
◆प्रकरण पर सियासत तेज,जांच अदालत में या बयानों के मंच पर

देने के बजाय ठोस तथ्यों के साथ अपनी आपत्तियां सामने रखनी चाहिए। कौन-सा साक्ष्य नजरअंदाज हुआ? किस बिंदु पर जांच में कमी है? किस तथ्य की अनदेखी की गई? जनता को यह बताया जाना चाहिए। उधर सरकार और भाजपा के पास भी केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। जनता का भरोसा सिर्फ इस वाक्य से नहीं बनता। जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता, अदालत में मजबूत पैरवी और पीड़ित परिवार को समय पर न्याय यही भरोसा पैदा करते हैं। क्योंकि जनता अब राजनीतिक दावों से आगे देखना चाहती है।

अंकिता प्रकरण में वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे परिवार के लिए हर नया बयान शायद पुराने जख्म को फिर खोलता है। इसलिए राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि किसी बेटी की त्रासदी को चुनावी पोस्टर, प्रेस नोट और राजनीतिक भाषण का विषय बनाने से न्याय नहीं मिलता और यहां एक असुविधाजनक सवाल दोनों पक्षों से है। अगर जांच सही है तो अदालत में साक्ष्य बोलने दीजिए। अगर जांच में कमी है तो ठोस तथ्य सामने रखिए। सिर्फ राजनीति हो रही है कहकर हर सवाल को खारिज कर देना भी लोकतांत्रिक जवाब नहीं है। और हर जांच को साजिश बताकर संदेह पैदा करना भी न्याय प्रक्रिया को मजबूत नहीं करता।

उत्तराखंड के लोगों ने इस प्रकरण में बहुत कुछ देखा है आक्रोश, आंदोलन, राजनीतिक आरोप, वादे और फिर लंबी कानूनी प्रक्रिया। अब जनता को बहस नहीं, परिणाम चाहिए। राजनीति अपनी जगह है। जांच अपनी जगह। अदालत अपनी जगह। अंकिता के मामले में सबसे जरूरी यह है कि जांच निष्पक्ष हो, साक्ष्यों के आधार पर हो और अदालत के सामने पूरा सच पहुंचे। दोषी कौन है, इसका फैसला राजनीतिक दलों के मंच से नहीं, कानून और न्यायालय की प्रक्रिया से होना चाहिए। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं रहेगा कि किस पार्टी ने कितनी प्रेस कांफ्रेंस कीं। सवाल यह रहेगा कि अंकिता को न्याय मिला या नहीं? और इस सवाल का जवाब किसी पार्टी के प्रवक्ता के पास नहीं, न्याय की प्रक्रिया के पास होना चाहिए।

अंतरराज्यीय गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधडी करने वाले अन्तर्रायीय गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कई एटीएम कार्ड व अन्य सामग्री बरामद कर ली। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

आज यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में संदिग्ध एवं अपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने तथा संदिग्धों की तलाश हेतु लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जनपद में संदिग्ध/अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की तलाश हेतु लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए प्रभावी कार्यवाही की रही है इसी क्रम में विकासनगर पुलिस को हरबर्टपुर चौक के पास गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि चार संदिग्ध व्यक्ति स्विफ्ट कार एवं मोटरसाइकिल से विकासनगर क्षेत्र में आए हुए हैं, जो एटीएम कार्ड बदलकर चोरी/धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा विकासनगर क्षेत्र में भी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पोंटा रोड हर्बर्टपुर स्थित ढालीपुर पुल से पहले आम के बगीचे के पास चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार में बैठे चार व्यक्तियों को रोककर चैक किया गया। कार सवार चारो व्यक्तियों की गतिविधिया संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस तथा अलग-अलग बैंकों के कई एटीएम कार्ड बरामद हुए, बरामद एटीएम कार्डो के संबंध में जानकारी करने पर उनके द्वारा उक्त एटीएम कार्डो को अलग-अलग लोगो से ठगी कर चोरी करना बताया गया। जिस पर चारों को मौके से गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध कोतवाली विकासनगर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग स्थानों पर एटीएम बूथों के आसपास घूमकर बुजुर्ग, महिलाओं एवं सीधे-सादे लोगों को अपना निशाना बनाते है। एटीएम से पैसा निकालते समय मदद करने के बहाने बुजुर्ग व्यक्तियों/महिलाओं के एटीएम कार्ड चतुराई से बदलकर पिन की जानकारी प्राप्त कर बाद में उनके बैंक खातों से धनराशि निकाल लेते थे। वह घटना स्थल से कुछ दूरी पर अपनी कार व बाइक खड़ी करते थे, जिससे घटना के बाद तुरन्त मौके आए फरार हो सके। चारों विकास नगर क्षेत्र में भी ठगी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में आए थे। पूछताछ में उनका पूर्व में हिमाचल प्रदेश, जम्मू, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर आदि स्थानों से एटीएम ठगी की घटनाओं में जेल जाना प्रकाश में आया है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास एवं अन्य घटनाओं में संलिप्तता के संबंध में जानकारी की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम जगमोहन पुत्र अजमेर, निवासी न्यू सरस्वती विहार, थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर, नीटू पुत्र नरेश, निवासी बुढाखेड़ा, थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर, सोनू पुत्र रमेश, निवासी पैरामाउंट के पास, जनपद सहारनपुर, आशु कुमार पुत्र श्यामलाल, निवासी मोहनपुरा/गुलाबनगर, रुड़की, जनपद हरिद्वार बताये। जिनके कब्जे से कुल 192 एटीएम/डेबिट कार्ड, विभिन्न बैंकों के 01 अवैध देसी तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 12 बोर बरामद हुए। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

चुनावी रण से पहले 'मीडिया मैनेजमेंट' एक्टिव

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियों का रिहर्सल शुरू कर दिया है। कहीं बूथ मजबूत किए जा रहे हैं, कहीं संगठन की बैठकें हो रही हैं और कहीं टिकट के दावेदार शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। लेकिन इस पूरी चुनावी तैयारी में एक ऐसा मोर्चा भी है, जहां भाजपा फिलहाल बाकी दलों से काफी आगे दिखाई दे रही है मीडिया मैनेजमेंट। अखबारों के न्यूजरूम तक पहुंचने वाली प्रेस विज्ञप्तियों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। भाजपा की ओर से एक दिन में पांच से दस तक विज्ञप्तियां पहुंच रही हैं। बयान, कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठकें, सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर हमले और स्थानीय गतिविधिया हर मुद्दे को मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश दिखाई दे रही है। इसके उलट कांग्रेस की तरफ से कई दिनों में महज एक-दो विज्ञप्तियां ही पहुंचती हैं। पार्टी के पास मुद्दे हैं, नेता हैं, बयान हैं और सरकार को घेरने के मौके भी हैं, लेकिन उन्हें लगातार और व्यवस्थित तरीके से मीडिया तक पहुंचाने की मशीनरी उतनी सक्रिय नजर नहीं आती। चुनाव में यह अंतर सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियों का नहीं, राजनीतिक संचार की तैयारी का संकेत है।

भाजपा ने लंबे समय से यह समझ लिया है कि चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता। चुनाव की लड़ाई अखबारों, टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफार्म और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। इसलिए पार्टी के पास संगठन के साथ-साथ संदेश पहुंचाने का तंत्र भी लगातार सक्रिय रहता है। एक कार्यक्रम हुआ नहीं कि तस्वीरें तैयार। नेता ने बयान दिया नहीं कि प्रेस नोट तैयार। सरकार ने कोई उपलब्धि गिनाई नहीं कि उसका प्रचार शुरू। विपक्ष ने कोई आरोप लगाया नहीं कि उसका जवाब भी तैयार। यानी भाजपा का संदेश है खबर खत्म होने से पहले हमारी प्रतिक्रिया खबर में होनी चाहिए। इसके सामने कांग्रेस का मीडिया तंत्र कई बार ऐसा दिखाई देता है जैसे पार्टी को खबर बनने के बाद खबर याद आती हो। कांग्रेस के पास बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, कानून-व्यवस्था, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार को घेरने के लिए उसके पास सामग्री की पूरी फाइल है। लेकिन सवाल यह है कि उस फाइल को रोज जनता तक पहुंचाने वाला कौन है?

राजनीति में मुद्दा होना पर्याप्त नहीं है। मुद्दे को जनता की भाषा में लगातार सामने रखना भी पड़ता है। कांग्रेस अगर सप्ताह में एक-दो बार प्रेस नोट जारी करके यह मान ले कि उसने विपक्ष की भूमिका निभा दी, तो भाजपा की लगातार चलने वाली मीडिया मशीनरी के सामने उसका संदेश स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ेगा और बाकी दल? उनकी स्थिति तो और भी कठिन है। उत्तराखंड क्रांति दल राज्य की अस्मिता, मूल निवास और क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीति को फिर से धार देने की कोशिश

◆भाजपा फुल एक्टिव, कांग्रेस सुस्त, बाकी दलों की आवाज कहां
◆मीडिया मैनेजमेंट के मोर्चे पर भाजपा सबसे आगे, कांग्रेस है पीछे
◆चुनाव से पहले कांग्रेस के पास मौके, लेकिन प्रचार मशीनरी बंद
◆भाजपा चला रही विज्ञप्ति-बाण, कांग्रेस का संचार तंत्र अभी सुस्त

कर रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठा सकती है। बसपा का अपना सामाजिक आधार है। वाम दलों के पास मुद्दों की कमी नहीं। छोटे क्षेत्रीय और नए राजनीतिक समूह भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में मौजूदगी के मामले में इनमें से अधिकांश दल या तो कभी-कभार दिखाई देते हैं या चुनाव के करीब आते ही सक्रिय होने की उम्मीद में बैठे हैं। यहीं सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि मीडिया कोई चुनावी लाउडस्पीकर नहीं है, जिसे मतदान से दो महीने पहले आन कर दिया जाए।

जनता को लगातार बताना पड़ता है कि पार्टी क्या सोचती है, क्या चाहती है और सत्ता में आने पर क्या करेगी। भाजपा इस मोर्चे पर फिलहाल बाकी दलों से आगे है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह स्थिति चेतावनी भी है और अवसर भी। अगर कांग्रेस सचमुच 2027 को गंभीरता से ले रही है तो उसे सिर्फ बड़े नेताओं के दौरों और प्रेस कान्फ्रेंस तक सीमित रहने के बजाय डेली मीडिया नैरेटिव बनाना होगा। हर दिन का एक मुद्दा, सरकार पर एक सवाल, जनता की एक समस्या और उसका राजनीतिक समाधान यह लगातार जनता तक जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव में जनता को वही दिखाई देता है जो लगातार दिखाई देता है। यहां एक और दिलचस्प सवाल है क्या मीडिया मैनेजमेंट चुनाव जिताता है?

सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन खराब मीडिया मैनेजमेंट चुनावी संदेश को जरूर कमजोर कर सकता है। भाजपा अगर रोज दस बातें जनता तक पहुंचा रही है और कांग्रेस रोज एक बात भी मुश्किल से पहुंचा रही है तो जनता के सामने किसकी मौजूदगी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है और छोटे दलों के लिए तो चुनौती और बड़ी है। उनके पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास खबरें नहीं हैं। आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय पत्रकारों और क्षेत्रीय मुद्दों के माध्यम से कम खर्च में भी मजबूत राजनीतिक संवाद बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए नियमितता, रणनीति और राजनीतिक संदेश की स्पष्टता।

उत्तराखंड की राजनीति में 2027 की जमीन तैयार हो रही है। भाजपा संगठन और मीडिया दोनों स्तर पर पहले से सक्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार विरोधी माहौल को राजनीतिक विकल्प में बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके संदेश की निरंतरता सवालों में है। यूकेडी और दूसरे छोटे दल जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, मगर उनकी आवाज का विस्तार सीमित है। आखिर चुनाव सिर्फ यह नहीं है कि कौन जनता के बीच गया। यह भी है कि कौन जनता के दिमाग में लगातार मौजूद रहा और मीडिया की इस लड़ाई में अभी तस्वीर साफ है। भाजपा रोज दस्तक दे रही है, कांग्रेस कभी-कभार दरवाजा खटखटा रही है और बाकी दल शायद यह इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख घोषित हो और दरवाजा अपने आप खुल जाए। लेकिन राजनीति में दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, उन्हें रोज खटखटाना पड़ता है।

'एक्स्ट्रा इनकम' का लाइसेंस
उत्तराखंड में डाक्टरों को भी जल्द ही मिलेगा शाम का बाजार

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह के बदले कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पद की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएगा। लेकिन धीरे-धीरे इस व्यवस्था में एक नया शब्द घुस आया हैकृएक्स्ट्रा इनकम। पहले यह शब्द फुसफुसाकर बोला जाता था। अब लगता है कि इसे व्यवस्था ने बाकायदा स्वीकार करना शुरू कर दिया है। पुलिस में ऊपर की कमाई की कहानियां पुरानी हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइल आगे बढ़ाने की अपनी फीस है। कहीं काम कराने की कीमत है, कहीं काम रोकने की कीमत। कहीं ठेका है तो कहीं कमीशन। कहीं परमिट है तो कहीं सिफारिश। जनता को धीरे-धीरे समझा दिया गया कि सरकारी नौकरी की असली कमाई वेतन पर्ची में नहीं, उसके बाहर है और अब बेचारे डाक्टर भी बच गए थे। सरकार ने कहा उन्हें भी शाम को मरीज देखने दीजिए।

खबर सुनकर शायद कोई कहेगा कि इसमें बुराई क्या है? डाक्टर हैं, मेहनत करेंगे, अतिरिक्त कमाई करेंगे। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर सरकारी अस्पताल की नौकरी के बाद उसी सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस होगी, तो मरीज सरकारी रहेगा या निजी? डाक्टर सरकारी रहेगा या निजी? अस्पताल सरकारी रहेगा या कमाई का साझा मंच? उत्तराखंड में सरकारी चिकित्सकों को शाम के समय सरकारी अस्पतालों में सशर्त निजी प्रैक्टिस की अनुमति देने की तैयारी है। यानी अब व्यवस्था का मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है दिन में सरकार की नौकरी, शाम को उसी व्यवस्था में निजी कमाई। इसे सुविधा कहिए, सुधार कहिए या डाक्टरों को रोकने की कोशिश। लेकिन जनता का सवाल इससे खत्म नहीं होता। क्योंकि सरकारी अस्पताल में आने वाला गरीब मरीज यह सोचकर आता है कि यहां उसे निजी अस्पताल की तुलना में राहत मिलेगी। वह डाक्टर की फीस और अस्पताल के खर्च से बचने की उम्मीद लेकर आता है। अगर उसी सरकारी परिसर में निजी प्रैक्टिस का रास्ता खुलता है तो सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी सेवा और निजी सेवा के बीच दीवार कहां होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी व्यवस्था धीरे-धीरे ऐसी दुकान बन जाए जिसमें काउंटर दो हों एक सरकार के नाम पर और दूसरा निजी कमाई के नाम पर?

यह सवाल डाक्टरों के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। डाक्टर मेहनत करते हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, दूरदराज के इलाकों में सेवाएं देते हैं। स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों की कमी भी वास्तविक समस्या है और सरकारी आंकड़ों में मेडिकल आफिसर और विशेषज्ञों के पदों पर रिक्तियां दर्ज हैं। लेकिन सवाल व्यवस्था का है। अगर डाक्टरों को रोकने के लिए उन्हें अतिरिक्त कमाई का रास्ता देना जरूरी हो गया है, तो अगला सवाल यह होना चाहिए कि पुलिस को क्या दिया जाएगा? फिर पटवारी क्यों पीछे रहे? फिर

❑मजबूरी से निकलकर एक्स्ट्रा इनकम बनी देशभर में अधिकार
❑डाक्टरों को निजी प्रैक्टिस की छूट से व्यवस्था पर उठेंगे सवाल

तहसील का कर्मचारी क्यों पीछे रहे? फिर वह क्लर्क क्यों पीछे रहे जिसकी मेज पर आपकी फाइल पड़ी है? फिर हर सरकारी विभाग में एक बोर्ड क्यों न लगा दिया जाए। सरकारी सेवा समय-सुबह से शाम तक और एक्स्ट्रा इनकम का समय-शाम के बाद। व्यंग्य लग रहा है? लेकिन खतरा यहीं है।

जब व्यवस्था किसी अनौपचारिक एक्स्ट्रा इनकम को रोकने में असफल होती है, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला भ्रष्टाचार और अनौपचारिक कमाई पर कठोर कार्रवाई। दूसरा उसे किसी न किसी रूप में वैध या स्वीकार्य बनाने का रास्ता। दूसरा रास्ता आसान है। जनता भी धीरे-धीरे अभ्यस्त हो जाती है। पहले लोग कहते थे बिना पैसे काम नहीं होता। फिर कहने लगे साहब की भी मजबूरी है। अब कहीं ऐसा न हो कि अगली पीढ़ी पूछेकृकि सरकारी नौकरी में एक्स्ट्रा इनकम कितनी है?यही असली खतरा है। सरकार को डाक्टरों के लिए अतिरिक्त कमाई का रास्ता खोलना है तो नियम इतने साफ होने चाहिए कि सरकारी सेवा की कीमत पर निजी कमाई का खेल न हो। मरीज को पहले यह अधिकार होना चाहिए कि उसे सरकारी अस्पताल में सरकारी सेवा किस कीमत पर और किस व्यवस्था में मिलेगी। क्योंकि सरकारी अस्पताल गरीब की मजबूरी नहीं, उसका अधिकार है।

सरकारी डाक्टर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होता। वह राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा होता है। जिस डाक्टर को जनता अपने टैक्स से वेतन देती है, उससे जनता को यह उम्मीद भी होती है कि उसका इलाज प्राथमिकता होगा, न कि उसकी जेब और यही सवाल पुलिस और दूसरे विभागों पर भी लागू होता है। सरकारी नौकरी अगर सेवा है तो सेवा की कीमत वेतन है। अगर वेतन कम है तो वेतन बढ़ाइए। काम का दबाव ज्यादा है तो व्यवस्था सुधारिए। डाक्टरों की कमी है तो भर्ती कीजिए। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं तो सुविधाएं बढ़ाइए। लेकिन हर समस्या का समाधान एक्स्ट्रा इनकम क्यों बनता जा रहा है?

कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय व्यवस्था की कमियों को कमाई का अवसर बनाकर छोड़ रही है? जनता को सरकारी अस्पताल में इलाज चाहिए, सरकारी दफ्तर में काम चाहिए, पुलिस से सुरक्षा चाहिए और विभागों से जवाबदेही। उसे यह नहीं चाहिए कि हर सेवा के साथ कोई एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जिस दिन सरकारी सेवा और निजी कमाई के बीच की रेखा मिट गई, उस दिन सबसे बड़ा नुकसान गरीब का होगा। फिर सरकारी अस्पताल अस्पताल नहीं रहेगा, सरकारी दफ्तर दफ्तर नहीं रहेगा और सरकारी नौकरी नौकरी नहीं रहेगी सब कुछ एक बाजार में बदल जाएगा और बाजार में सबसे कमजोर हमेशा वही होता है जिसके पास पैसे कम होते हैं। इसलिए सवाल डाक्टरों को अतिरिक्त कमाई की अनुमति देने से ज्यादा बड़ा है। क्या सरकार सरकारी व्यवस्था को मजबूत कर रही है या धीरे-धीरे जनता को यह समझा रही है कि हर सरकारी सेवा के पीछे एक एक्स्ट्रा देना सामान्य बात है? क्योंकि 'एक्स्ट्रा इनकम' की यह छोटी-सी दरार कल पूरी व्यवस्था की दीवार में बड़ा छेद बन सकती है।

पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के लिए कारीगरों को किया जागरूक

अल्मोड़ा(आरएनएस)। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विकासखंड हवालबाग में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के एमएसएमई-डीएफओ हल्द्वानी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 150 से अधिक पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों, ब्रांडिंग और डिजिटल विपणन के माध्यम से कारीगरों के व्यवसाय को नई पहचान दिलाना था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उपलब्ध टूलकिट, वित्तीय सहायता, ऋण सुविधा, उद्यम पंजीकरण, उत्पाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्यूआर कोड आधारित शिपिंग एवं ट्रैकिंग सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने और आधुनिक डिजाइन व गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दौरान कारीगरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यावसायिक उपयोग से भी अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि एआई टूल्स की मदद से उत्पाद डिजाइन तैयार करने, डिजिटल कंटेंट बनाने और ग्राहकों की पसंद के अनुरूप विपणन रणनीति विकसित की जा सकती है। कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना के पांच लाभार्थियों के लिए मौके पर ही क्यूआर कोड भी तैयार किए गए। संवादात्मक सत्र में कारीगरों ने व्यवसाय पंजीकरण, सरकारी योजनाओं, ऋण, सब्सिडी, टूलकिट और एआई आधारित तकनीकों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से समाधान किया। कार्यक्रम में एमएसएमई-डीएफओ हल्द्वानी के सहायक निदेशक विनोद कुमार, संदीप प्रियदर्शी, अग्रणी जिला प्रबंधक अनिरुद्ध शाह, जिला उद्योग केंद्र, इंडिया पोस्ट, रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर एवं राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कारीगर और शिल्पकार मौजूद रहे।

डिप्लोमा फार्मासिस्ट 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध

रुद्रपुर(आरएनएस)। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड (राजकीय फार्मेसी अधिकारी सेवा संघ) की ऊधमसिंह नगर शाखा ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 15 सितंबर तक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और महासंघ पदाधिकारियों को मांगों के समर्थन में पत्र लिखे जाएंगे, जबकि मांगें पूरी नहीं होने पर फार्मेसी अधिकारी काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बीएन बेलवाल और जिला मंत्री केसी विश्वकर्मा ने कहा कि संघ की प्रमुख मांगों में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर करने पर प्रथम पद का वेतनमान प्रदान करना, स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए पूर्व में सृजित 391 पदों को क्रियाशील करना, राज्य में फार्मेसी प्रैक्टिस रेग्युलेशन-2015 के प्रावधानों को लागू करना और ओडिशा और असम की तर्ज पर फार्मेसी अधिकारियों को कार्य के लिए अधिकृत किया जाना शामिल है।इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान फार्मेसी अधिकारियों को मिलने वाले देयकों और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई है। संघ के कार्यक्रम के अनुसार 31 अगस्त 2026 तक जनप्रतिनिधियों एवं महासंघ के पदाधिकारियों को मांगों के समर्थन में पत्र लेखन किया जाएगा। इसके बाद 1 से 15 सितंबर तक सभी सदस्य काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए संघ की 23 अगस्त 2026 को जनपद मुख्यालय में आम बैठक आयोजित की जाएगी।

मंत्री कैड़ा संग नियमितीकरण के लिए सीएम से मिले उपनल कर्मी

हल्द्वानी(आरएनएस)। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के नेतृत्व में उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 15 से 20 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अब भी हर साल अनुबंध नवीनीकरण कराना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उपनल कर्मचारियों का संविदा अनुमन्यता प्रकरण करीब 30 वर्षों से लंबित है। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा की निरंतरता और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की।उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था, न्यूनतम वेतनमान, महंगाई भत्ता और एरियर देने, हर साल अनुबंध नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने तथा कार्य के अनुरूप पद का वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्यक्ष अनुबंध के बावजूद नियमितीकरण और न्यायालयीन अधिकार सुरक्षित रखने, पूर्व सेवा को निरंतर सेवा मानने, समकक्ष पद नहीं होने पर अन्य विभागों के पदों को आधार बनाने और न्यूनतम वेतनमान की 10 वर्ष की शर्त समाप्त करने की मांग भी रखी गई। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी मांगें मजबूती से रखीं।

मालदेवता में सास-बहू की जोड़ी ने राखी कारोबार से मचाई धूम

संवाददाता

देहरादून। रायपुर विकासखंड के मालदेवता क्षेत्र की सास-बहू लीला रावत और अलका रावत की जोड़ी राखी कारोबार में अपनी अलग पहचान बना रही है।

रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही देहरादून में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही हैंडमेड राखियों की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकासखंड की महिलाएं राखी निर्माण को स्वरोजगार का जरिया बनाकर न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में रायपुर विकासखंड के मालदेवता क्षेत्र की सास-बहू लीला रावत और अलका रावत की जोड़ी राखी कारोबार में अपनी अलग पहचान बना रही है।

रायपुर ब्लॉक की नई दिशा महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के अंतर्गत आशा किरण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दोनों महिलाएं मिलकर आकर्षक डिजाइन की राखियां तैयार कर रही हैं। इस वर्ष उन्होंने दो हजार से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक करीब 1,500 राखियां तैयार की जा चुकी हैं।

लीला और अलका ने बताया कि पिछले वर्ष प्रशासन के सहयोग से उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ। दोनों ने करीब 1,200 राखियां तैयार कर सीधे बाजार में बिक्री की, जिससे उन्हें लगभग 25 हजार रुपये का मुनाफा हुआ। उत्साह बढ़ने के बाद इस वर्ष उन्होंने राखी कारोबार को और विस्तार देने का लक्ष्य तय किया है। अलका रावत ने पिछले वर्ष प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपनी सास लीला के साथ स्वरोजगार की राह चुनी। दोनों ने मालदेवता क्षेत्र में 'विनी वंडर्स क्रिएशन' नाम से दुकान शुरू की है। एनआरएलएम के सहयोग से शुरू किए गए इस स्वरोजगार के माध्यम से वे राखियों के साथ अन्य हस्तनिर्मित एवं स्थानीय उत्पादों का भी कारोबार कर रही हैं।

अलका के अनुसार समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आय का बेहतर अवसर मिला है। साथ ही सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर वह स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हैंडमेड राखियों की बिक्री अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है। 'विनी वंडर्स क्रिएशन' के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ग्राहकों से राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं।

महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त ऑर्डर तैयार कर ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। इससे उनके कारोबार को स्थानीय बाजार के साथ-साथ डिजिटल बाजार में भी विस्तार मिल रहा है। वहीं, सहसपुर विकासखंड के सक्षम क्लस्टर की महिलाएं भी राखियां तैयार कर रही हैं। उनकी राखियों को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शित किया जा रहा है और सेलाकुई, सहसपुर तथा विकासनगर क्षेत्र में भी अच्छा बाजार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा देहरादून के तीन-चार प्रमुख मॉलों में भी राखियों के स्टॉल लगाए जाएंगे।

उन्होंने आमजन से अपील की कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार की गई हस्तनिर्मित राखियों और अन्य उत्पादों की खरीदारी कर उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करें। सहायक परियोजना निदेशक अनीता पंवार ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एनआरएलएम से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं बेहतर गुणवत्ता वाली राखियां बाजार में उपलब्ध करा रही हैं। सहसपुर, रायपुर और डोईवाला विकासखंड की महिलाओं को राखियों की बिक्री के लिए अच्छा बाजार मिल रहा है।

शब्द सामर्थ्य -044

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे

1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।

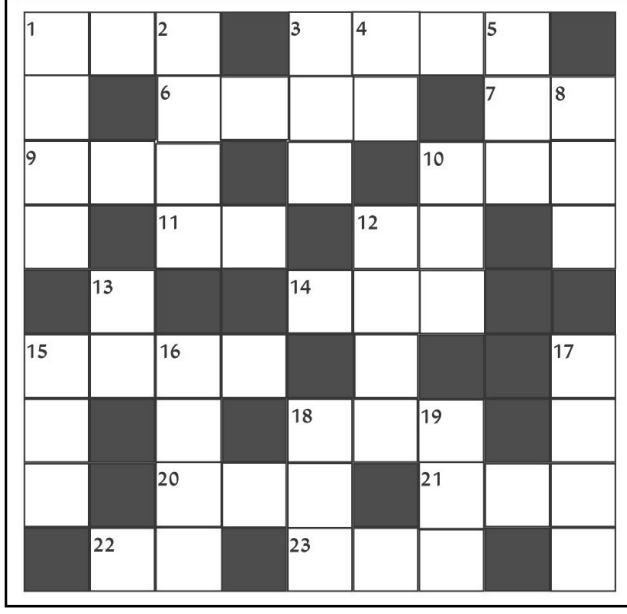

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 43 का हल

ज	ल		आ	वा	जा	ही		
मा		खू	ब		दू	र	स्थ	
ना	दा	न		सा	ग		ल	क्ष्य
	न	ख		त	र	ल		
	वी	रा	न			च	ट	क
	र	ब		आ	ज	क	ल	
			आ	ग		दा	ना	
	अ	ग	र	म	ग	र		क्रो
भा	भी		ती	न			व	ध

स्किन और बालों को सुंदर बनाता है मोगरे का फूल

मोगरे का फूल कई मायनों में फायदेमंद है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण सदियों से ही इसका उपयोग किया जाता है। खासतौर से एशियाई और पूर्वी संस्कृतियों में लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। मोगरे की अनोखी खुशबू हर किसी को प्रभावित करती है।

यह फूल बालों और चेहरे के लिए बेहद लाभकारी है। यह न सिर्फ डियोड्रेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि त्वचा और बालों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। मोगरे की खुशबू मूड को बेहतर बनाती है और दिमाग को तरोताजा रखती है।

मोगरे का इस्तेमाल ऑयल के रूप में किया जाता है। इसमें कीटोन की सांद्रता कम होती है। यह सौम्य और सुगंधित खुशबू प्रदान करता है और नैचुरल डियोड्रेंट का काम करता है।

स्ट्रेच मार्क और दाग-धब्बे को दूर करने के लिए मोगरे के तेल को पेट्रोलियम जेली और नारियल तेल के साथ उपयोग करना फायदेमंद होता है। यह ड्राई स्किन की समस्या से छुटकारा देता है और त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखता है।

कोमल और मुलायम त्वचा के लिए मोगरे का तेल फायदेमंद है। पानी में कुछ बूंद मोगरे के तेल की मिलाकर नहाने से त्वचा मुलायम होती है। इस तेल में एलोवेरा मिलाकर लगाने से त्वचा मॉइश्चराइज होती है।

मोगरे की चाय घाव और खरोंच को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा मोगरे का तेल रैशेज, सनबर्न और त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद है।

स्कैल्प हेल्दी होने पर बाल अपने आप स्वस्थ और मजबूत होते हैं। जैस्मीन के रस में नारियल तेल, बादाम का तेल या जोजोबा ऑयल मिलाकर लगाने से बालों में नमी बनी रहती है और रूसी एवं टूटते बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है।

इस तरह जैस्मीन त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद है। जैस्मीन का अर्क, फूल और ऑयल का उपयोग हेल्दी बालों के लिए किया जा सकता है। 10-15 मोगरे के फूल को पानी में भिगोकर पानी बनाएं। इस पानी से बालों को धोने से बाल मुलायम होते हैं। इस पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर शैंपू और कंडीशनर के रुप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बालों में इसका तेल लगाने से बाल घुंघराले होते हैं। मोगरे की पत्तियों का रस बालों को जड़ से मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही बालों को टूटने और झड़ने से बचाता है। इसकी ताजी पत्तियों के रस को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से बाल लंबे, घने और मोटे होते हैं।

खाती हैं चावल और सफेद पास्ता, तो हो जाइए सावधान!

क्या आपको भी सफेद पास्ता और चावल बहुत भाता है? अगर हां तो आपको इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार सफेद पास्ता खाने से महिलाओं को समय से पहले मीनोपोज होने का डर रहता है। ब्रिटेन में हुए एक शोध में चेतावनी दी गई है कि सफेद पास्ता और चावल के अधिक सेवन से मीनोपोज समय से करीब डेढ़ वर्ष पहले हो सकती है। एपिडेमिलॉजी एंड कम्युनिटी हैल्थ नाम के जर्नल में प्रकाशित शोध में पता चला है कि सेहतमंद चीजें मसलन ऑयली फिश और ताजी फलियां जैसे कि मटर और हरे बीन्स खाने से मीनोपोज देर से होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के शोधकर्ताओं ने खानपान और मीनोपोज के बीच संबंध तलाशने के लिए अध्ययन किया। इस शोध में ब्रिटेन में रहने वाली 14,150 महिलाओं को शामिल किया गया। शोधकर्ता याश्वी डननेराम का कहना है कि यह इस किस्म का पहला शोध है जिसमें ब्रिटेन की महिलाओं में न्यूट्रिशंस, खाद्य समूहों की विविधता और नेचुरल मीनोपोज की आयु के बीच संबंध तलाशा गया। खानपान संबंधी प्रश्नावली के अलावा महिलाओं के प्रजनन के इतिहास और सेहत के बारे में जानकारी जुटाई गई। चार वर्ष बाद शोधकर्ताओं ने उन महिलाओं की डाइट का आकलन किया जिन्हें इस बीच मीनोपोज हो गया था। ब्रिटेन में मीनोपोज की औसत आयु 51 वर्ष है। करीब 900 महिलाओं (40 से 65 वर्ष) को इस बीच प्राकृतिक रूप से मीनोपोज हुआ। आकलन में पाया गया कि जिन महिलाओं ने ऑयली फिश का अधिक सेवन किया और उन्हें कम से कम तीन साल देर से मीनोपोज हुआ। जबकि पाया गया कि रिफाइंड पास्ता और चावल खाने वाली महिलाओं में मीनोपोज डेढ़ साल पहले ही हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफलीड्स में प्रोफेसर जानेट केड ने कहा कि मीनोपोज का कुछ महिलाओं के लिए सेहत पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

सिटी ब्यूटीफुल से पंजाबी सिनेमा में लौटीं अपूर्वा अरोड़ा!

लोकप्रिय अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा ने आगामी पंजाबी क्राइम थ्रिलर फिल्म सिटी ब्यूटीफुल से पंजाबी सिनेमा में वापसी की है। पंजाबी सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री फिल्म को घर वापसी बताया। अभिनेत्री ने बताया कि इससे पहले वे पंजाबी सिनेमा में गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ डिस्को सिंह में नजर आई थीं, जिसके बाद से वे अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही थीं, जो उन्हें सच में इंडस्ट्री में वापस लाए और सिटी ब्यूटीफुल वह प्रोजेक्ट निकला। अभिनेत्री अपूर्वा ने कहा, यह फिल्म मेरे लिए सच में एक घर वापसी जैसा है। इस फिल्म की कहानी ने मुझे तुरंत मुझसे कनेक्ट कर दिया। मैं अभी अपने कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं कह सकती हूं कि यह एक शानदार अनुभव रहा है। हम चंडीगढ़ और मोहाली में शूटिंग कर रहे हैं। सेट पर हर कोई बहुत अच्छा और सपोर्टिव है। हमारे डायरेक्टर ने पूरे प्रोसेस को बहुत आरामदायक बना दिया है और हर दिन सेट पर आना बहुत अच्छा लगा है।

अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी सिनेमा से की, जिस वजह से पंजाब हमेशा से ही मेरे लिए खास रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने अपनी भावनाएं शेयर करते हुए कहा, इतने वर्षों बाद वापस आना अजीब लगता है, हालांकि शूटिंग खत्म होने के बाद मैं अमृतसर के गोल्डन टेंपल आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाऊंगी। यह इस खूबसूरत सफर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। अपूर्वा अरोड़ा हाल ही में हरियाणा की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म मोमाकू में नजर आई थीं। इस फिल्म का पूरा नाम मोटर, माचिस और कटर है। यह एक सस्पेंस, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है, जिसमें अभिनेत्री ने पिंकी नाम की मुख्य भूमिका निभाई हैं। इस फिल्म में उनके साथ जतिन सरना, यशपाल शर्मा और तुषार दत्त जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे।

रामायण का हिस्सा बनकर खुशी से झूमी रकुल प्रीत सिंह

रणबीर कपूर और साई पल्लवी अभिनीत फिल्म रामायण का हिस्सा बनकर रकुल प्रीत सिंह बेहद खुश हैं। फिल्म में काम करने को लेकर अभिनेत्री बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुशी जताई है।

रकुल प्रीत सिंह ने इस प्रोजेक्ट को सिनेमा से भी आगे की एक यात्रा बताया है। रकुल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने रामायण के भव्य ट्रेलर लॉन्च इवेंट की झलकियां शेयर कीं। साथ ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बारे में बात की। इवेंट में रकुल प्रीत येलो कलर की ड्रेस में नजर आईं।

उन्होंने लिखा है, एक ऐसी चीज का हिस्सा बनना सम्मान की बात है, जो जिंदगी और सिनेमा से भी कहीं बड़ी है। हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी रामायण। हम दुनिया के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एहसास सचमुच शब्दों से परे है। आप सभी के हमारे साथ इस दुनिया में कदम रखने का बेसब्री से इंतजार है।

बता दें कि रकुल प्रीत सिंह को नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में शूर्पणखा की भूमिका में देखा जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में होंगे। वहीं, साई पल्लवी माता सीता का रोल कर रही हैं। एक्टर यश रावण की अहम भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी। पहला हिस्सा इस साल दिवाली पर आएगा। वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 में दिवाली के अवसर पर रिलीज होगा।

...जब माधुरी दीक्षित से मिलीं वामिका गब्बी!

बॉलीवुड अभिनेत्री वामिका गब्बी बचपन से जिस अभिनेत्री को वह अपना आइकॉन मानती थीं, आखिरकार उनसे मिलने का उनका सपना सच हो गया। दरअसल, वामिका ने बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा माधुरी दीक्षित से मुलाकात की, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो के साथ वामिका गब्बी ने बताया कि वह 13 साल की उम्र से माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन रही हैं और उनसे मिलने का सपना लंबे समय से संजोए हुए थीं। सालों बाद जब यह सपना पूरा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वीडियो की शुरुआत में वामिका, माधुरी दीक्षित के मशहूर गाने धक-धक के आइकॉनिक स्टेप को करती नजर आती हैं तभी माधुरी दीक्षित पीछे से आती हैं और प्यार से उन्हें गले लगा लेती हैं। अचानक अपने सामने बचपन की आइकॉन को देखकर वामिका इमोशनल हो जाती हैं और तुरंत उन्हें कसकर गले लगा लेती हैं।

वीडियो में वामिका ब्लू कलर के एथनिक आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आईं, जबकि माधुरी दीक्षित गुलाबी साड़ी में हमेशा की तरह बेहद आकर्षक दिखीं। वीडियो में माधुरी, वामिका से उनका हालचाल पूछती भी दिखती हैं।

वीडियो शेयर करते हुए वामिका ने लिखा, मेरे सबसे करीबी दोस्त जानते हैं कि 13 साल की उम्र वाली वामिका के लिए यह पल कितना जादुई था। आखिरकार मेरी मुलाकात द माधुरी दीक्षित से हुई। मैंने उन्हें मम्मी-पापा से भी मिलवाया और बचपन के कई किस्से सुनाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे मेरे बचपन का कितना खूबसूरत हिस्सा रही हैं।

अगर वामिका गब्बी के करियर की बात करें तो उन्होंने बहुत कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। साल 2007 में इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म जब वी मेट से उन्होंने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत की। फिल्म में उनका किरदार छोटा था, लेकिन यहीं से उनके अभिनय करियर की नींव रखी गई। इसके बाद वह लव आज कल, मौसम और बिट्टू बॉस जैसी फिल्मों में नजर आईं और धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाती चली गईं।

बॉलीवुड के अलावा वामिका ने पंजाबी और मलयालम सिनेमा में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। पंजाबी फिल्म तू मेरा 22 मैं तेरा 22 और मलयालम फिल्म गोधा में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। हाल ही में वह फिल्म पति पत्नी और वो दो में नजर आई थीं।

डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग की समीक्षा बैठक

अल्मोड़ा (आरएनएस)। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्य को लेकर सुझाव लिए गए तथा अभियान के दौरान सामने आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जनपद में अब तक 98,529 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 78,867 नोटिसों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धीकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सूची में दर्ज सभी प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शेष नोटिसों, दावों और आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बीएलओ और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर देते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को नियमित समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी संजय कुमार सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कैलाश गुरुरानी, पूरन रौतेला एवं अन्य मौजूद रहे।

वरिष्ठ नागरिक आपके द्वार अभियान में 13 नए सदस्य जुड़े

हल्द्वानी(आरएनएस)। वरिष्ठ नागरिक जनकल्याण समिति की ओर से चलाए जा रहे 'वरिष्ठ नागरिक आपके द्वार' अभियान के तहत द्वितीय बैठक हुई। समिति अध्यक्ष भुवन भास्कर पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के स्थापना, उद्देश्यों और वरिष्ठ नागरिकों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर 86 वर्षीय बुजुर्ग दंपती देवी दत्त तिवारी और उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित किया गया। समिति की स्थायी सदस्यता ग्रहण करने वाले मीरा तिवारी, भुवन चंद तिवारी, पुष्पा पांडे, देवेंद्र प्रसाद पांडे, त्रिवेणी माधव शर्मा, जीवन चंद्र मुनगली, सुशीला मुनगली, जगदीश चंद्र पाठक, लीलाधर सती, आनंद सिंह बिष्ट, विशन सिंह, सतीश चंद्र जोशी और हरिश्चंद्र सिंह ऐरी को स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया गया।अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक अक्तूबर को राजकीय स्तर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजय कुमार का आभार जताया। संचालन महामंत्री डीके पांडे ने किया। यहां इंद्र सिंह निगल्टिया, दया किशन बल्यूटिया, डीके पंत, विष्णु सिंह रावत, रमेश चंद पांडे, बीडी जोशी, एलएम लोहनी, एचपी जोसेफ, किरण कुमार कबड़वाल, राजेंद्र सिंह बिष्ट, सुमन चंद जोशी, एडी डोर्बी, दिनेश चंद पंतोला, पद्मादत्त पांडे, आनंद सिंह भाकुनी आदि मौजूद रहे।

सू- दोकू क्र.044

	6	3		8		1		4
8			3		4		7	
	4			5		8		
3		8			1		4	
	1			4		9		7
		4			2		1	
1				3		4		8
	8		2		9		3	
		9		1		2		5

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.43 का हल

6	7	9	2	4	5	3	1	8
2	1	8	3	7	6	9	5	4
7	6	4	5	2	8	1	3	9
3	8	1	6	9	7	2	4	5
9	2	5	4	1	3	8	6	7
8	3	7	9	6	4	5	2	1
5	4	2	8	3	1	7	9	6
1	9	6	7	5	2	4	8	3
4	5	3	1	8	9	6	7	2

बरख से गणेशीगैर तक शेष मार्ग के निर्माण की मांग को जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

अल्मोड़ा(आरएनएस)। लमगड़ा और हवालबाग विकासखंड के करीब 20 गांवों के ग्रामीणों ने नारी निकेतन (बख) से दमुवाधारा होते हुए गणेशीगैर-धारानौला मुख्य मोटर मार्ग तक शेष 500 मीटर पैदल मार्ग का निर्माण और गणेशीगैर पुलिया के चौड़ीकरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरा मार्ग बरसात के दौरान लोगों के लिए खतरे का कारण बना हुआ है। गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि किशोरी बालिका सदन (बख) से होकर गुजरने वाला यह मार्ग विश्वनाथ मंदिर, श्मशान घाट और शहर तक पहुंचने का प्रमुख सार्वजनिक पैदल मार्ग है। इसका उपयोग लमगड़ा और हवालबाग विकासखंड के करीब 20 गांवों के लोग प्रतिदिन करते हैं। मार्ग का लगभग 500 मीटर हिस्सा अधूरा होने से बरसात में कीचड़ और फिसलन के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक मनोज तिवारी के प्रयासों से वर्ष 2023-24 में जिला योजना से 15 लाख रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 10 लाख रुपये स्वीकृत होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने मार्ग का अधिकांश निर्माण कराया, लेकिन शेष हिस्सा और गणेशीगैर स्थित पुलिया का चौड़ीकरण अब भी लंबित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के अभाव में कार्य पूरा नहीं हो सका। ग्रामीणों ने जिला योजना अथवा अन्य मद से धनराशि स्वीकृत कर शेष मार्ग पर सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के साथ गणेशीगैर पुलिया का चौड़ीकरण कराने की मांग की। उनका कहना है कि निर्माण पूरा होने से हजारों लोगों को धार्मिक स्थलों, श्मशान घाट और शहर तक सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जनहित को देखते हुए शेष मार्ग के निर्माण और पुलिया चौड़ीकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में गोपाल सिंह चौहान, चंदन ढैला, शिवेंद्र गोस्वामी, मदन सिंह मेर, पार्षद विजय कुमार भट्ट, कैलाश गुरुरानी, गोधन सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान आरती बिष्ट, पूरन रौतेला, रवि कुमार, प्रकाश बिष्ट, दयाशंकर, त्रिलोक बोरा, नवीन सनवाल, बृजेश कुमार, शंकर लाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे।

तदर्थ समिति की बैठक में डेलिगेट निर्वाचन पर मंथन

रुद्रपुर(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के ऊधम सिंह नगर के लंबे समय से लंबित निर्वाचन को गति देने के लिए बीआरसी रुद्रपुर में जनपदीय तदर्थ समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी डेलिगेट निर्वाचन की तैयारियों, प्रक्रिया और चार विकासखंडों में चुनाव कराने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और आपसी सहमति के साथ शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया।ऊधम सिंह नगर का निर्वाचन विभिन्न विवादों के चलते लंबे समय से लंबित था। न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद उप निबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, देहरादून की ओर से जिले में निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।इसके तहत गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर और जसपुर विकासखंडों में डेलिगेट निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। बैठक में चारों विकासखंडों में डेलिगेट निर्वाचन की प्रक्रिया, आगामी कार्रवाई और निर्वाचन को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। बैठक में देवेंद्र चौधरी, गुलाब सिंह सिरोही, शैलेश जोशी, नितेंद्र सिंह गिल, अमित त्यागी, पंकज चौहान, नागेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।

बीमा योजनाओं में टिहरी जिले में एक लाख खाते घटे, जांच के निर्देश

नई टिहरी(आरएनएस)। जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में बैंकों की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने कम प्रगति वाले बैंक अधिकारियों को गति बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य अंतिम तिमाही से पहले पूरा करने के निर्देश दिए।जिला सभागार में आयोजित बैठक में सीडीओ ने जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में खातों की संख्या करीब एक लाख घटने पर नाराजगी जताई। बैंक अधिकारियों को संबंधित खातों की विस्तृत जांच करने को कहा। गांवों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क कर बीमा की किस्त जमा होने और खातों में कमी के कारणों की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में उद्यान विभाग को सितंबर माह के अंत तक कम से कम 25 आवेदन बैंकों को उपलब्ध कराने, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में अधिक आवेदन भेजने के निर्देश दिए।

5 से 30 सितंबर तक होगी मां नंदा की बड़ी जात

चमोली (आरएनएस)। मां नंदा के सिद्धपीठ कुरुड़ से इस वर्ष बड़ी जात का आयोजन 5 से 30 सितंबर तक किया जाएगा। जात को भव्य और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए बड़ी जात आयोजन समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कुरुड़ स्थित मां नंदा मंदिर में रंग-रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं समिति ने जात के निर्जन पड़ावों के रास्तों के सुधारीकरण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बड़ी जात समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र सिंह रावत (सेनि.) ने बताया कि समिति ने जिला प्रशासन, शासन और पीएमओ के प्रतिनिधियों से भी बड़ी जात में शामिल होने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बड़ी जात में कुरुड़ से डोली जाएगी। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने गोपेश्वर में पत्रकार वार्ता कर कहा कि मां नंदा की बड़ी जात दिव्य और भव्य तरीके से आयोजित की जाएगी। इस आयोजन को राजनीतिक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

किसानों को गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों का दिया प्रशिक्षण

अल्मोड़ा(आरएनएस)। पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र, काफलीगैर (बागेश्वर) द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत आयोजित सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।

13 से 19 अगस्त तक चले इस प्रशिक्षण में विभिन्न गांवों के 38 किसानों को गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मी कांत के निर्देशन तथा कृषि विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. निर्मल हेडाऊ के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फल, सब्जी और पुष्प फसलों की पौध तैयार करने की उन्नत विधियों से परिचित कराया गया। प्रशिक्षण समन्वयक एवं केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राज कुमार ने फलदार पौधों की कलम तैयार करने, उन्नत कृषि तकनीकों और उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी। वहीं डॉ. नवल किशोर सिंह ने डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, प्राकृतिक खेती और चारा उत्पादन पर मार्गदर्शन दिया। पादप सुरक्षा विशेषज्ञ हरीश चंद्र जोशी ने कीट एवं रोग प्रबंधन, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन की जानकारी साझा की। डॉ. अमित कुमार ने कृषक उत्पादक समूह, कृषि व्यवसाय और विपणन के विषय में जानकारी दी, जबकि संस्कृति सिंह ने पोषण वाटिका और मूल्य संवर्धन पर व्याख्यान दिया। वरिष्ठ शोध अध्येता डॉ. राजेश कुमार मीणा ने सब्जियों की पौधशाला प्रबंधन का प्रदर्शन कराया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र और सब्जियों के बीज वितरित किए गए। प्रशिक्षण से पूर्व और बाद में हुए मूल्यांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में प्रक्षेत्र प्रबंधक नीरज जोशी, कार्यालय सहायक मनोज कुमार सहित महेश सिंह, सौरभ सिंह, बहादुर सिंह, राजेंद्र सिंह और सुरेश लाल का योगदान रहा।

विकास, निवेश और सुशासन से अग्रणी बन रहा उत्तराखण्डः सीएम धामी

संवाददाता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द इकोमिक टाम्स वर्ल्ड लीडर्स फॉरम 2026 का शुभारम्भ करते हुए कहा कि विकास, निवेश व सुशासन से उत्तराखण्ड अग्रणी बन रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित "द इकोमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फॉरम 2026" कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड के विकास मॉडल, समान नागरिक संहिता, सुशासन, रोजगार, निवेश, पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास, नवाचार और बुनियादी ढांचे सहित राज्य की विकास यात्रा पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य ने देश के सामने सुशासन और समान अधिकारों का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद समाज में सकारात्मक वातावरण बना है और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों के अधिकारों को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड से निकली समान नागरिक संहिता की गंगा अब देश के अन्य राज्यों को भी समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की ैंकिंग में उत्तराखण्ड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में भी राज्य ने निवेश के लिए बेहतर नीतिगत वातावरण तैयार करने की दिशा में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की पर्यटन क्षमता को राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और आदि कैलाश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा के प्रथम चरण में ही 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में करीब 4.80 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। आदि कैलाश क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में नवाचार नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, वही भविष्य की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उत्तराखण्ड सरकार हर क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड केवल बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि कुंभ जैसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी जनवरी 2027 के हरिद्वार कुंभ के आयोजन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को आगामी जनवरी 2027 के कुंभ में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

60 की उम्र में नौकरी खत्म, अफसरों...

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

लिए सरकारी व्यवस्था में नई भूमिकाएं निकल आती हैं, तो उसके मन में सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। सरकार को इस व्यवस्था के लिए एक साफ नीति बनानी चाहिए।

रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति अपवाद हो, परंपरा नहीं। हर पुनर्नियुक्ति के साथ कारण सार्वजनिक हो। पद की अवधि तय हो। काम का स्पष्ट दायरा हो। प्रदर्शन की समीक्षा हो। और जहां काम किसी नियमित सेवा अधिकारी या नए विशेषज्ञ से कराया जा सकता है, वहां सिर्फ पुराने प्रशासनिक संपर्कों के आधार पर नियुक्ति न हो। क्योंकि लोकतंत्र में अनुभव जरूरी है, लेकिन अवसरों का दरवाजा हमेशा एक ही पीढ़ी के लिए खुला रहना जरूरी नहीं है। उत्तराखंड को अब यह तय करना होगा कि सरकारी सेवा का मतलब 60 साल की उम्र में खत्म होने वाली नौकरी है या फिर कुछ लोगों के लिए सरकारी व्यवस्था में चलती रहने वाली दूसरी पारी? अगर दूसरी पारी जरूरी है तो उसके नियम सबके सामने होने चाहिए। वरना जनता यही पूछेगी कि सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुआ है या सिर्फ पदनाम से?

मेरे सपनों का उत्तराखंड' अभियान को मिला ऐतिहासिक जनसमर्थन, 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भेजे निबंध

संवाददाता

देहरादून। 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' अभियान को प्रदेश के विद्यार्थियों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यभर से अब तक 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपने निबंध एवं सुझाव पोर्टल पर जमा कर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर अपना विजन साझा किया है।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर शुरू किए गए 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' अभियान को प्रदेश के विद्यार्थियों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यभर से अब तक 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने अपने निबंध एवं सुझाव पोर्टल पर जमा कर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर अपना विजन साझा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 10 अगस्त को प्रदेशभर के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लगभग तीन लाख विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन संवाद करते हुए उनसे आह्वान किया था कि वे बताएं कि आने वाले वर्षों में वे अपने उत्तराखंड को किस रूप में देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के इस आह्वान के बाद सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ अभियान में भागीदारी की। विद्यार्थियों ने पर्यटन, रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक सहित आठ प्रमुख विषयों पर अपने सुझाव और नए विचार प्रस्तुत किए हैं। खास बात यह है कि ये केवल निबंध नहीं, बल्कि उत्तराखंड की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और भविष्य के प्रदेश को लेकर उनकी सोच का दस्तावेज बन रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों से प्राप्त अच्छे और व्यावहारिक सुझावों का स्वयं अवलोकन किया जाएगा तथा उपयोगी विचारों को राज्य की नीतियों एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं में शामिल करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 140 श्रेष्ठ विचारों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सचिवों के साथ अपने विचारों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन विद्यार्थियों के साथ स्वयं संवाद कर उनके विजन और अनुभवों को सुनेंगे। इसके साथ ही श्रेष्ठ विद्यार्थियों को करियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग और अन्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर निबंध जमा करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। अभियान में प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के साथ ही सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है। अभियान के संयोजक डॉ. राहुल अग्रवाल ने बताया कि नई पीढ़ी को सीधे राज्य की विकास प्रक्रिया और नीति निर्माण की सोच से जोड़ने की यह एक अभिनव पहल है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार प्रविष्टियां प्राप्त हो रही हैं। 24 अगस्त निबंध जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं अभियान की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी केवल विकास योजनाओं की लाभार्थी न रहे, बल्कि 'विकसित उत्तराखंड' की संकल्पना और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार भी बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "हमारे विद्यार्थी केवल उत्तराखंड का भविष्य नहीं हैं, बल्कि उनके विचार आज के उत्तराखंड को भी नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' के माध्यम से हम नई पीढ़ी की सोच को सुन रहे हैं। युवाओं के अच्छे और व्यावहारिक सुझावों को प्रदेश के विकास में स्थान दिया जाएगा। हमारा संकल्प है कि युवा जिस उत्तराखंड का सपना देख रहे हैं, उसे साकार करने में उन्हें भी सहभागी बनाया जाए।"

एएचटीयू टीम ने स्कूली बच्चों को पढाया बाल व महिला सुरक्षा का पाठ

संवाददाता

उत्तरकाशी। एएचटीयू व मनेरी कोतवाली पुलिस की टीम ने बच्चों को बाल व महिला सुरक्षा का पाठ पढाया।

आज यहां मानव तस्करी की रोकथाम, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश, महिला एवं बाल अपराधों की प्रभावी रोकथाम तथा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में ए.एच.टी.यू. व कोतवाली मनेरी की टीम द्वारा राजकीय जूनियर हाईस्कूल सिल्ला, भटवाड़ी में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं को महिला अपराध, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, साइबर अपराध एवं नशा उन्मूलन के संबंध में जागरूक करते हुए आवश्यक सावधानियों एवं महत्वपूर्ण पुलिस हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। टीम द्वारा छात्र-छात्राओं को मानव तस्करी से जुड़े खतरों, बचाव के उपायों तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को अपरिचित व्यक्तियों की बातों में न आने, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से सावधान रहने तथा किसी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि अथवा परिस्थिति की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया।

बारिश ने खोली ट्रिपल इंजन सरकार की पोल

हमारे संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के काँवली स्थित शास्त्री नगर में उस सड़क का क्षेत्रवासियों के साथ दौरा किया, जिसका वीडियो बारिश के दौरान वाहनों और ऑटो के पानी में बहने के कारण वायरल हुआ था। उन्होने क्षेत्रवासियों से मौके पर बातचीत कर जलभराव की गंभीर समस्या और उससे हो रहे नुकसान की जानकारी ली।

वर्षों से नहीं बना ड्रेनेज प्लानः थापर

कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कहा कि शास्त्री नगर में हर वर्ष बारिश के दौरान जलभराव होना भाजपा सरकार के ट्रिपल इंजन के फेलियर का जीता-जागता उदाहरण है। नालियों की समय पर सफाई नहीं होती, ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और बारिश का पानी निकालने के लिए कोई प्रभावी स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा में भाजपा के 35 वर्षों के शासन के बावजूद हजारों लोगों की इस मूलभूत समस्या के समाधान के लिए आज तक एक समग्र ड्रेनेज प्लान तक नहीं बनाया जा सका।

उन्होने कहा कि शास्त्री नगर क्षेत्र में कैंट विधानसभा के चार वार्ड-39, 40, 41 एवं 42 में हजारों लोग निवास करते हैं, बावजूद इसके क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस और स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बारिश के दौरान उनके घरों में लगातार पानी घुसता है और उन्हें हर साल अपने परिवार, घर और सामान की सुरक्षा की चिंता रहती है। इस बार लगभग प्रत्येक घर प्रभावित हुआ।

अभिनव थापर ने कहा कि यह केवल जलभराव की समस्या नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। थापर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही शास्त्री नगर और आसपास के क्षेत्रों की जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तथा वैज्ञानिक ड्रेनेज व्यवस्था और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित नहीं की गई, तो कांग्रेस क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी।

जनता को हर साल जलभराव की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्षेत्र के दौरे के दौरान बिमलेश वर्मा, अवधेश कुमार, मालती देवी, कमला रावत, सीता भट्ट सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

शराब कैंटीन संचालक पर बीच सड़क में बरसाई गोलियां, मौत

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। उत्तराखण्ड के मैदानी जिले इन दिनों गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजायमान है। बीते दो दिन पूर्व जहां राजधानी दून की सड़कों पर बदमाशों द्वारा गोलियां बरसाई गयी वहीं एक बार फिर बीती रात ध र्मनगरी हरिद्वार की सड़क पर बदमाशो का ताडव सामने आया है। यहां बदमाशों द्वारा सरेराह शराब कैंटीन संचालक पर गोलिया बरसाकर हत्या कर दी गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, ढंडेरा निवासी अमन लंबे समय से क्षेत्र में शराब की कैंटीन का संचालन कर रहे थे। बीती देर रात उन्होंने अपनी कैंटीन बंद की और घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अमन पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। गोलियां लगते ही अमन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल अमन को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई करते हुए घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस कोतवाली के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में कांबिंग ऑपरेशन चलाया गया। देर रात तक हालांकि किसी ठोस सुराग का पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। वहीं

हत्या की खबर फैलते ही ढंडेरा और आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और पुलिस थाने का घेराव कर दिया। भीड़ ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में इस तरह की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल बन गया है।

कार की टक्कर से एक महिला की मौत, दो लोग हिरासत में

हमारे संवाददाता

देहरादून। सड़क दुर्घटना में देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी व बाइक सवार दो महिलाएं घायल हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गयी जबकि दूसरी का उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने कार सवार दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार बीती देर रात थाना राजपुर पुलिस को सूचना मिली कि कैनाल रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो मौके पर कार क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क किनारे खडी थी तथा स्कूटी व मोटरसायकिल मौके पर क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थी। मौके पर मौजूद लोगो ने बताया कि कार के चालक ने सडक किनारे खडी स्कूटी एंव बाइक में टक्कर मार दी थी जिससे स्कूटी व मोटर साइकिल पर बैठी महिलाओं को चोटे आयी है,जिन्हे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मौके से कार चालक सुमित यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी काठबंगला बस्ती भाग-2 थाना राजपुर देहरादून व उसके साथी हाशिम को हिरासत मे लिया गय। चालक सुमित यादव ने बताया कि काठबंगला से कैनाल रोड को आते हुए उसकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाए, जिस कारण उसकी कार सड़क के किनारे खडे वाहन से टकरा गयी। दुर्घटना से संबंधित कार को कब्जे लेकर थाना दाखिल किया गया है। उक्त दुर्घटना में स्कूटी मे बैठी महिला श्रीमती नैना राजपूत की उपचार के दौरान मैक्स अस्पताल में मृत्यु हो गई है तथा अन्य महिला श्रीमती निधि कश्यप का दून अस्पताल मे उपचार चल रहा है।

अखिलेश-मायावती समेत 52 नेताओं को मिली बुलेटप्रूफ जैकेट

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाया है। गृह मंत्रालय की सलाह पर यूपी के सुरक्षा मुख्यालय ने राज्य के 52 प्रमुख नेताओं को करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत वाली हाई-टेक बुलेटप्रूफ जैकेट मुहैया कराई हैं।

सुरक्षा मुख्यालय ने पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट सौंपी, जिससे कुल संख्या 52 हो गई है। सुरक्षा केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता श्नंदीश, संजय निषाद, ओपी राजभर, रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस सुरक्षा व्यवस्था में योगी सरकार के 11 कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विध ानसभा का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त हो रहा है। नियमानुसार, अगले यानी 19वीं विधानसभा के चुनाव फरवरी- मार्च 2027 के दौरान आयोजित होने प्रस्तावित हैं। चुनाव की घोषणा जनवरी 2027 की शुरुआत में हो सकती है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं।

निर्दलीय विधायक का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा

हमारे संवाददाता

उत्तरकाशी। यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आज दूसरे दिन जिला प्रशासन कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। विधायक ने जिला योजना में कथित 10 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने हेतू लिखित आश्वासन देने की मांग को लेकर प्रशासन से प्रत्यक्ष वार्ता करने की मांग की है।

विधायक और उनके समर्थक निर्धारित समय पर डीएम कार्यालय पहुँचे, तो डीएम दफ्तर के भीतर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की अनुपस्थिति को लेकर तीखा सवाल उठाया गया। विधायक ने प्रश्न किया कि जब मैंने पूर्व में बता दिया था कि आज मैं डीएम कार्यालय आऊँगा, तब डीएम साहब कार्यालय से गायब क्यों हैं? संजय डोभाल ने जिला योजना में 10 प्रतिशत कमीशन लगाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचार सीधे-सीधे विकास योजनाओं और आम जनता के हितों से छेड़छाड़ है। उन्होंने मांग की है कि भ्रष्टाचार में नामजद अधिकारियों और बिचोलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, प्रभावित योजनाओं का जनप्रतिनिधि के समक्ष फिर से वितरित कराई जाए। विधायक ने यह भी कहा कि वे शांति एवं सभ्य तरीके से वे अपनी मांगें रख रहे हैं, पर यदि प्रशासन ने लिखित आश्वासन नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लेकर संबंधित गांवों तक व्यापक विरोध-प्रदर्शन किए जाएँगे।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को दी एसआईआर पर विस्तृत जानकारी

संवाददाता

देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने राजनैतिक दलों को एसआईआर पर विस्तृत जानकारी दी।

आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई एवं राजनैतिक दलों के सुझाव प्राप्त किए गए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बैठक में बताया कि ड्राफ्ट

रोलमें शामिल कुल 71 लाख मतदाताओं में से अनमैप्ड और विसंगति वाले 24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे जिसके कम में 15 लाख से अधिकतम नोटिसों की सुनवाई कर दी गई है, शेष पर कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण रुप से नियमनुसार संपादित की जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को बताया प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने 9 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की पर्यवेक्षण अधिकारी के तौर पर अतरिक्त तैनाती की गई है। बैठक में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल, राजकुमार पुरोहित, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मनोज रावत, मौ. सुलेमान अंसारी, बीएसपी से सत्यपाल, सतेंद्र, जसपाल, सतेंद्र चोपड़ा, आम आदमी पार्टी से श्याम बाबू पांड्य, सीपीआई (एम) अनंत आकाश उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।